(ग) यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों की सम्बन्धित भाषा विषयक योग्यत की जांच का क्या मापदण्ड होगा ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) से (ग). इस मंत्रालय के विभिन्न विभागों में पत्रकारिता सम्बन्धी पद, केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड १ से ग्रेड ४ तक में संवर्गित है। इनमें अनेक पदों के लिये किसी न किसी भारतीय भाषा में प्रवीणता आवश्यक है। ग्रेड २ को छोड़ कर शेष सभी ग्रेडों में संधारण भर्ती के लिये लिखित परीक्षाओं में कुछ पर्चों का उत्तर अंग्रेजी में और कुछ का भारतीय भाषाओं में देना होता है। इन सभी पर्चों में और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर योग्यताक्रम निर्धारित किया जाता है।

ग्रेड २ में भर्ती भारतीय प्रशासन सेवा आदि, परीक्षा के परिणामों के आधार पर की जाती है, जिसमें भारतीय भाषा का पर्चा अनिवार्य नहीं है। जो चुने हुए उम्मीदवार केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड २ में नियुक्त किए जाते हैं, उनको एक साल प्रशिक्षण दिया जाता है और इस अवधि में उनको एक विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ती है जिसमें भारतीय भाषा की भी परीक्षा होती है।

ग्रेड ४ के आरम्भिक गठन के लिए १७१ स्थानों में भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग ने हाल में विज्ञापन निकाला था। इसकी लिखित परीक्षा में दो पर्चों के उत्तर अंग्रेजी में और एक पर्चे का सम्बन्धित भारतीय भाषा में देने की व्यवस्था है। साक्षात्कार के लिए केवल वही उम्मीदवार बुलाये जायेंगे, जो लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम नम्बर प्राप्त करेंगे।

Resolution on Southern Rhodesia

1675. Shrimati Savitri Nigam: Will the **Prime Minister** be pleased to state the name of the countries which are the signatories to the draft resolution in the Trusteeship Committee on Southern Rhodesia which Britain had vetoed in the Security Council?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): The following 36 countries were the original signatories to the draft resolution in the Trusteeship Committee (Fourth Committee) of the General Assembly on Southern Rhodesia which had been earlier vetoed by Britain in the Security Council:—

Algeria, Burundi, Cameroon, Ceylon, Chad, Chile, Dahomey, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Ivory Coast, Jamaica, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Morocco, Nepal, Nigeria, Philippines, Rwanda, Senegal, Somalia, Sudan, Syria, Tanganyika, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Republic, Upper Volta, Yemen, Yugoslavia.

Subsequently, Burma, Cambodia, Central African Republic, Libya, Malaysia, Niger, Pakistan and Sierra Leone joined as co-sponsors, raising the total number of signatories to 44.

International Cooperation Year

1676. Shrimati Savitri Nigam:
Shri Maheswar Naik:

Will the **Prime Minister** be pleased to state the names of the countries which have supported the Prime Minister's call for designation of a year of International Cooperation?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru):

The following 21 countries introduced a draft resolution in December, 1962, in the U.N. General Assembly supporting the Prime Minister's call